भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2186
दिनांक 12 फरवरी, 2026

ईंधन बिक्री केंद्रों हेतु आवंटन

†2186. **श्री मनोज कुमारः**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को आवंटित मौजूदा पेट्रोल पंपों, सीएनजी स्टेशनों और एलपीजी गैस एजेंसियों की ओएमसी-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है और प्रतिशत कितना है;

(ख) वर्ष 2014 से वर्ष 2026 की अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पेट्रोल पंपों, सीएनजी स्टेशनों और एलपीजी एजेंसियों के आवंटन संबंधी विभिन्न चरणों में लंबित पड़े हुए मामलों की ओएमसी-वार, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ग) पेट्रोल पंपों, सीएनजी स्टेशनों और एलपीजी गैस एजेंसी के आवंटन के लिए रिक्तियों और बैकलॉग रिक्तियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, ओएमसी-वार और वर्ग-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार या ओएमसी का उक्त रिक्तियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए कोई विशेष अभियान चलाने या विज्ञापन जारी करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे विशेष अभियानों और विज्ञापनों के लिए समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ग): सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) ने सूचित किया है कि खुदरा बिक्री केंद्र (आरओ) नेटवर्क को बढ़ाना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ताकि पूरे देश में पेट्रोल और डीज़ल जैसे मोटरिंग ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। ओएमसी ने जून/जुलाई 2023 में देश भर में आरओ खोलने के लिए 49,960 स्थलों के लिए विज्ञापन दिया, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित स्थल भी शामिल हैं। विज्ञापन में दिए गए जगहों में एससी/एसटी श्रेणी के लिए बैकलॉग स्थल भी शामिल हैं।

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की नियुक्ति भी एक लगातार चलने वाला प्रक्रिया है और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए स्थलों की पहचान बिक्री की संभावना के आधार पर की जाती है, जो उन्हें व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाती है। तथापि, यह लगातार सुनिश्चित किया जाता है कि संबंधित पीएसयू ओएमसी द्वारा कुल मिलाकर आरक्षण तब भी बनाए रखा जाए, जब जगहों का विवर्गीकरण पूर्व के रोस्टर से किया जाता है, जिसमें नए रोस्टर से 'ओपन' श्रेणी के तहत एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की संबंधित संख्या को 'एससी/एसटी' और 'ओबीसी' श्रेणी में, जैसा भी लागू हो, बदला जाता है।

सीएनजी स्टेशन की स्थापना नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास का हिस्सा है और यह काम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) से प्राधिकृत कम्पनी करती हैं, जो श्रेणी के हिसाब से आवंटन संरक्षित नहीं करती हैं। दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार, प्राधिकृत कम्पनी ने पूरे देश में 8,456 सीएनजी स्टेशन बनाए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) ने खुदरा बिक्री केंद्रों (आरओज़) के लिए दिनांक 28.06.2023 से नवीन "डीलरशिप चयन दिशानिर्देश" और दिनांक 23.06.2016 से "एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चयन के लिए एकीकृत दिशानिर्देश" लागू की हैं। इन दोनों दिशानिर्देश में, अन्य बातों के साथ-साथ, खुदरा बिक्री केंद्र डीलरशिप और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन में निम्नलिखित राज्यों को छोड़कर अन्य सभी में एससी/एसटी के लिए 22.5% और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान है,:

खुदरा बिक्री केंद्र-

राज्य	एसटी श्रेणी को दिए जाने वाले नियमित और ग्रामीण आरओ डीलरशिप का प्रतिशत	शेष % 'ओपन' श्रेणी को दिया जाएगा
अरुणाचल प्रदेश	70	30
मेघालय	80	20
नागालैंड	80	20
मिजोरम	90	10

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप

राज्य	एसटी श्रेणी को दिए जाने वाले आरक्षण का प्रतिशत	महिला श्रेणी के लिए %	शेष % 'ओपन' श्रेणी को दिया जाएगा
अरुणाचल प्रदेश	49	30	21
मेघालय	56	30	14
नागालैंड	56	30	14
मिजोरम	63	30	7

पीएसयू ओएमसीज़ (आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल)/राज्य/यूटी-वार एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य श्रेणी को दिए गए मौजूदा आरओ और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की संख्या और प्रतिशत अनुलग्नक-1 और अनुलग्नक -2 में दिए गए हैं।\

पीएसयू ओएमसीज़ ने आगे बताया है कि जिन आरओज़ और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी किए गए हैं, उन्हें आरंभ करने में विभिन्न स्तर होते हैं, जिसमें आवश्यक संवेधानिक मंज़ूरी लेना, स्थल पर निर्माण आदि शामिल हैं। आरओज़ और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को आरम्भ करने की प्रक्रिया में तीव्रता लाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्ष 2014 से 2026 की अवधि के दौरान (दिनांक 01.02.2026 की स्थिति के अनुसार), पीएसयू ओएमसी द्वारा एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य श्रेणी को दिए गए आरओज़ के लिए 28,008 एलओआई और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए 154 एलओआई चालू करने के विभिन्न स्तरों पर हैं। पीएसयू ओएमसीज़

(आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल/ राज्य/यूटी-वार आरओ और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए ऐसे एलओआई की संख्या श्रेणी के हिसाब से अनुलग्नक-3 और अनुलग्नक-4 में दी गई है।

आरओज़ के आवंटन में आरक्षित श्रेणी का अंश भरने के लिए पीएसयू ओएमसी द्वारा किए गए प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) एससी/एसटी और ओबीसी आवेदक के लिए आवेदन शुल्क और सुरक्षा जमा ओपेन श्रेणी की तुलना में कम रखा गया है।

(ii) एससी/एसटी आवेदक को सिर्फ़ विज्ञापित क्षेत्र में समुचित भूमि की पहचान करनी होगी और पीएसयू ओएमसीज़ को खरीदने या दीर्घकालिक पट्टा पर देने के लिए प्रस्ताव देना होगा।

(iii) एससी/एसटी श्रेणी के तहत आरओ को कॉर्पस फंड योजना के तहत विकसित किया जाता है, जहाँ खुदरा बिक्री केंद्र की संपूर्ण अवसंरचना ओएमसीज़ द्वारा विकसित की जाती है।

(iv) एससी/एसटी एलओआई धारकों को आरओज़ के चालू होने के बाद कार्यशील पूँजी ऋण प्रदान किया जाता है।

(v) एससी/एसटी के लंबित एलओआई को खत्म करना, जिसमें देश में कहीं भी अपनी पसंद के स्थल पर भूमि की व्यवस्था करने का एक-बार विकल्प दिया जाएगा, बशर्ते दी गई भूमि तकनीकी-व्यावसायिक व्यवहार्यता को पूरा करे और एससी/एसटी के लंबित एलओआई धारको को सौंपने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अस्थायी कोकोज के लिए विनिवेश किया जाएगा। यह योजना दिनांक 31.3.2022 तक लागू थी।

(घ) जी नहीं।

****

अनुलग्नक -1

"ईंधन बिक्री केंद्रों हेतु आवंटन" के संबंध में श्री मनोज कुमार द्वारा दिनांक 12.02.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2186 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुलग्नक।

दिनांक 01.02.2026 की स्थिति के अनुसार खुदरा बिक्री केंद्रों का राज्य/यूटी/श्रेणी-वार संख्या - बीपीसीएल									
	आरओ की संख्या					आरओ का %			
राज्य	कुल आरओ	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओबीसी #	खुला / अन्य*	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	खुला / अन्य
अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	1,190	159	59	92	880	13	5	8	74
अरुणाचल प्रदेश	73	0	49	0	24	0	67	0	33
असम	340	21	52	41	226	6	15	12	66
बिहार	992	102	11	76	803	10	1	8	81
चंडीगढ़	10	1	0	0	9	10	0	0	90
छत्तीसगढ	663	35	70	82	476	5	11	12	72
दिल्ली	107	7	0	0	100	7	0	0	93
गोवा	61	1	0	1	59	2	0	2	97
गुजरात	1,483	97	195	122	1,069	7	13	8	72
हरियाणा	862	136	0	76	650	16	0	9	75
हिमाचल प्रदेश	160	25	5	14	116	16	3	9	73
जम्मू और कश्मीर	218	10	20	11	177	5	9	5	81
झारखंड	559	22	40	59	438	4	7	11	78
कर्नाटक	1,891	199	89	181	1,422	11	5	10	75
केरल	684	100	10	27	547	15	1	4	80
लद्दाख	7	0	4	0	3	0	57	0	43
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	1,830	146	122	200	1,362	8	7	11	74
महाराष्ट्र	2,704	260	126	192	2,126	10	5	7	79
मणिपुर	49	2	8	10	29	4	16	20	59
मेघालय	81	1	62	0	18	1	77	0	22
मिजोरम	15	0	12	0	3	0	80	0	20
नागालैंड	38	0	28	0	10	0	74	0	26
ओडिशा	686	49	43	49	545	7	6	7	79
पुदुचेरी	49	4	0	3	42	8	0	6	86
पंजाब	837	140	0	41	656	17	0	5	78
राजस्थान	1,527	178	96	143	1,110	12	6	9	73
सिक्किम	32	0	2	4	26	0	6	13	81
तमिलनाडु	2,168	311	13	212	1,632	14	1	10	75
तेलंगाना	1,255	145	94	126	890	12	7	10	71
त्रिपुरा	22	1	5	2	14	5	23	9	64
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	13	0	2	0	11	0	15	0	85
उत्तर प्रदेश	3,202	475	9	425	2,293	15	0	13	72
उत्तराखंड	206	18	8	18	162	9	4	9	79
पश्चिम बंगाल	928	98	20	59	751	11	2	6	81

स्रोत - बीपीसीएल

*ओपन/अन्य शामिल हैं
(i) ओपन, रक्षा, पुलिस, सहकारी समितियों, सरकारी निकायों, कोको, उत्कृष्ट खिलाड़ियों, स्वतंत्रता सेनानियों को आवंटित खुदरा दुकानें।
(ii) मार्केटिंग प्लान से पहले, डीलरशिप बिना रिज़र्वेशन के दिए जाते थे।
(iii) ऑपरेशन विजय के परिवारों को आवंटित डीलरशिप।
ओबीसी कैटेगरी के तहत 27% का रिज़र्वेशन 24.07.2012 से शुरू किया गया था और ओएमसीज़ ने बाद के एडवर्टाइज़मेंट में इसे लागू किया।

अनुलग्नक 1

"ईंधन बिक्री केंद्रों हेतु आवंटन" के संबंध में श्री मनोज कुमार द्वारा दिनांक 12.02.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2186 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुलग्नक।

दिनांक 01.02.2026 की स्थिति के अनुसार खुदरा बिक्री केंद्रों का राज्य/यूटी/श्रेणी-वार संख्या – आईओसीएल									
	आरओ की संख्या					आरओ का %			
राज्य	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओबीसी #	खुला / अन्य*	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	खुला / अन्य
अंडमान और निकोबार	22	0	3	1	18	0.00	13.64	4.55	81.82
आंध्र प्रदेश	1806	240	80	78	1408	13.29	4.43	4.32	77.96
अरुणाचल प्रदेश	189	0	141	0	48	0.00	74.60	0.00	25.40
असम	823	52	110	62	599	6.32	13.37	7.53	72.78
बिहार	2043	230	18	168	1627	11.26	0.88	8.22	79.64
चंडीगढ़	25	4	0	0	21	16.00	0.00	0.00	84.00
छत्तीसगढ़	1007	47	115	96	749	4.67	11.42	9.53	74.38
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	27	1	2	0	24	3.70	7.41	0.00	88.89
दिल्ली	193	22	0	0	171	11.40	0.00	0.00	88.60
गोवा	44	2	0	2	40	4.55	0.00	4.55	90.91
गुजरात	2219	164	231	191	1633	7.39	10.41	8.61	73.59
हरियाणा	2119	271	1	135	1712	12.79	0.05	6.37	80.79
हिमाचल प्रदेश	388	57	18	32	281	14.69	4.64	8.25	72.42
जम्मू और कश्मीर	369	16	16	26	311	4.34	4.34	7.05	84.28
झारखंड	832	33	72	95	632	3.97	8.65	11.42	75.96
कर्नाटक	2913	336	96	217	2264	11.53	3.30	7.45	77.72
केरल	1293	160	20	90	1023	12.37	1.55	6.96	79.12
लद्दाख	24	1	14	1	8	4.17	58.33	4.17	33.33
लक्षद्वीप	4	0	0	0	4	0.00	0.00	0.00	100.00
मध्य प्रदेश	2801	213	221	334	2033	7.60	7.89	11.92	72.58
महाराष्ट्र	2915	252	144	221	2298	8.64	4.94	7.58	78.83
मणिपुर	151	3	39	20	89	1.99	25.83	13.25	58.94
मेघालय	194	0	133	0	61	0.00	68.56	0.00	31.44
मिजोरम	80	0	62	0	18	0.00	77.50	0.00	22.50
नागालैंड	161	0	97	0	64	0.00	60.25	0.00	39.75
उड़ीसा	1329	121	115	112	981	9.10	8.65	8.43	73.81
पुदुचेरी	108	12	0	5	91	11.11	0.00	4.63	84.26
पंजाब	2129	262	0	49	1818	12.31	0.00	2.30	85.39
राजस्थान	2864	291	223	279	2071	10.16	7.79	9.74	72.31
सिक्किम	32	0	8	1	23	0.00	25.00	3.13	71.88
तमिलनाडु	3091	463	23	243	2362	14.98	0.74	7.86	76.42
तेलंगाना	1679	237	123	115	1204	14.12	7.33	6.85	71.71
त्रिपुरा	119	7	13	10	89	5.88	10.92	8.40	74.79
उत्तर प्रदेश	6049	929	18	600	4502	15.36	0.30	9.92	74.43
उत्तराखंड	427	44	9	26	348	10.30	2.11	6.09	81.50
पश्चिम बंगाल	1680	215	38	123	1304	12.80	2.26	7.32	77.62

स्रोत - बीपीसीएल

*ओपन/अन्य शामिल हैं

(i) ओपन, रक्षा, पुलिस, सहकारी समितियों, सरकारी निकायों, कोको, उत्कृष्ट खिलाड़ियों, स्वतंत्रता सेनानियों को आवंटित खुदरा दुकानें।

(ii) मार्केटिंग प्लान से पहले, डीलरशिप बिना रिज़र्वेशन के दिए जाते थे।

(iii) ऑपरेशन विजय के परिवारों को आवंटित डीलरशिप।

ओबीसी कैटेगरी के तहत 27% का रिज़र्वेशन 24.07.2012 से शुरू किया गया था और ओएमसीज़ ने बाद के एडवर्टाइज़मेंट में इसे लागू किया।

अनुलग्नक 1

"ईंधन बिक्री केंद्रों हेतु आवंटन" के संबंध में श्री मनोज कुमार द्वारा दिनांक 12.02.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2186 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुलग्नक।

दिनांक 01.02.2026 की स्थिति के अनुसार खुदरा बिक्री केंद्रों का राज्य/यूटी/श्रेणी-वार संख्या – - एचपीसीएल									
	आरओ की संख्या					आरओ का %			
राज्य	कुल आरओ	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओबीसी #	खुला / अन्य*	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	खुला / अन्य
अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	1494	202	74	101	1117	13.52	4.95	6.76	74.77
अरुणाचल प्रदेश	39	0	27	0	12	0.00	69.23	0.00	30.77
असम	256	21	38	30	167	8.20	14.84	11.72	65.23
बिहार	786	118	9	72	587	15.01	1.15	9.16	74.68
चंडीगढ़	13	1	0	0	12	7.69	0.00	0.00	92.31
छत्तीसगढ	803	38	93	93	579	4.73	11.58	11.58	72.10
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	25	1	2	2	20	4.00	8.00	8.00	80.00
दिल्ली	99	4	0	0	95	4.04	0.00	0.00	95.96
गोवा	46	5	0	2	39	10.87	0.00	4.35	84.78
गुजरात	1352	95	191	111	955	7.03	14.13	8.21	70.64
हरियाणा	1084	153	0	85	846	14.11	0.00	7.84	78.04
हिमाचल प्रदेश	210	35	7	15	153	16.67	3.33	7.14	72.86
जम्मू और कश्मीर	212	15	20	13	164	7.08	9.43	6.13	77.36
झारखंड	501	23	62	71	345	4.59	12.38	14.17	68.86
कर्नाटक	1684	270	81	178	1155	16.03	4.81	10.57	68.59
केरल	843	114	9	70	650	13.52	1.07	8.30	77.11
लद्दाख	8	0	4	0	4	0.00	50.00	0.00	50.00
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	1684	130	175	189	1190	7.72	10.39	11.22	70.67
महाराष्ट्र	2611	271	134	233	1973	10.38	5.13	8.92	75.56
मणिपुर	15	1	3	3	8	6.67	20.00	20.00	53.33
मेघालय	56	0	36	0	20	0.00	64.29	0.00	35.71
मिजोरम	25	0	24	0	1	0.00	96.00	0.00	4.00
नागालैंड	31	0	14	0	17	0.00	45.16	0.00	54.84
ओडिशा	591	43	42	67	439	7.28	7.11	11.34	74.28
पुदुचेरी	48	7	0	2	39	14.58	0.00	4.17	81.25
पंजाब	1095	192	0	41	862	17.53	0.00	3.74	78.72
राजस्थान	1888	201	155	206	1326	10.65	8.21	10.91	70.23
सिक्किम	12	0	3	0	9	0.00	25.00	0.00	75.00
तमिलनाडु	1879	279	12	177	1411	14.85	0.64	9.42	75.09
तेलंगाना	1332	169	94	122	947	12.69	7.06	9.16	71.10
त्रिपुरा	17	1	3	1	12	5.88	17.65	5.88	70.59
उत्तर प्रदेश	2979	506	9	392	2072	16.99	0.30	13.16	69.55
उत्तराखंड	254	32	5	17	200	12.60	1.97	6.69	78.74
पश्चिम बंगाल	727	97	20	46	564	13.34	2.75	6.33	77.58

स्रोत - बीपीसीएल

*ओपन/अन्य शामिल हैं
(i) ओपन, रक्षा, पुलिस, सहकारी समितियों, सरकारी निकायों, कोको, उत्कृष्ट खिलाड़ियों, स्वतंत्रता सेनानियों को आवंटित खुदरा दुकानें।
(ii) मार्केटिंग प्लान से पहले, डीलरशिप बिना रिज़र्वेशन के दिए जाते थे।
(iii) ऑपरेशन विजय के परिवारों को आवंटित डीलरशिप।
ओबीसी कैटेगरी के तहत 27% का रिज़र्वेशन 24.07.2012 से शुरू किया गया था और ओएमसीज़ ने बाद के एडवर्टाइज़मेंट में इसे लागू किया।

अनुलग्नक - 2

"ईंधन बिक्री केंद्रों हेतु आवंटन" के संबंध में **श्री मनोज कुमार** द्वारा दिनांक 12.02.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2186 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुलग्नक।

दिनांक 01.02.2026 की स्थिति के अनुसार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की संख्या एससी/एसटी/ओबीसी/ओपन-ओएमसी

आईओसीएल

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	वितरकों की कुल संख्या	एससी श्रेणी के अंतर्गत वितरक	एसटी श्रेणी के अंतर्गत वितरक	ओबीसी कैटेगरी के तहत डिस्ट्रीब्यूटर #	खुला/ अन्य *	एससी कैटेगरी के तहत % डिस्ट्रीब्यूटर	एसटी कैटेगरी के तहत % डिस्ट्रीब्यूटर	ओबीसी कैटेगरी के तहत % डिस्ट्रीब्यूटर	ओपन/अन्य कैटेगरी के तहत % डिस्ट्रीब्यूटर
आंध्र प्रदेश	467	85	22	27	333	18.2%	4.7%	5.8%	71.3%
अरुणाचल प्रदेश	81	0	52	0	29	0.0%	64.2%	0.0%	35.8%
असम	434	32	65	35	302	7.4%	15.0%	8.1%	69.6%
बिहार	1049	206	12	144	687	19.6%	1.1%	13.7%	65.5%
छत्तीसगढ़	264	19	34	25	186	7.2%	12.9%	9.5%	70.5%
दिल्ली	192	27	0	1	164	14.1%	0.0%	0.5%	85.4%
गोवा	5	1	0	0	4	20.0%	0.0%	0.0%	80.0%
गुजरात	558	42	51	40	425	7.5%	9.1%	7.2%	76.2%
हरियाणा	298	59	0	24	215	19.8%	0.0%	8.1%	72.1%
हिमाचल प्रदेश	150	16	3	6	125	10.7%	2.0%	4.0%	83.3%
झारखंड	326	25	37	26	238	7.7%	11.3%	8.0%	73.0%
कर्नाटक	579	84	23	46	426	14.5%	4.0%	7.9%	73.6%
केरल	350	46	5	21	278	13.1%	1.4%	6.0%	79.4%
मध्य प्रदेश	802	71	60	71	600	8.9%	7.5%	8.9%	74.8%
महाराष्ट्र	607	68	70	60	409	11.2%	11.5%	9.9%	67.4%
मणिपुर	99	1	25	8	65	1.0%	25.3%	8.1%	65.7%
मेघालय	52	0	29	0	23	0.0%	55.8%	0.0%	44.2%
मिजोरम	59	0	43	0	16	0.0%	72.9%	0.0%	27.1%
नागालैंड	70	0	49	0	21	0.0%	70.0%	0.0%	30.0%

ओडिशा	435	37	41	60	297	8.5%	9.4%	13.8%	68.3%
पंजाब	477	79	0	24	374	16.6%	0.0%	5.0%	78.4%
राजस्थान	659	79	56	71	453	12.0%	8.5%	10.8%	68.7%
सिक्किम	23	0	5	0	18	0.0%	21.7%	0.0%	78.3%
तमिलनाडु	920	179	6	87	648	19.5%	0.7%	9.5%	70.4%
तेलंगाना	362	46	15	23	278	12.7%	4.1%	6.4%	76.8%
त्रिपुरा	85	5	17	8	55	5.9%	20.0%	9.4%	64.7%
उत्तर प्रदेश	2230	450	2	219	1559	20.2%	0.1%	9.8%	69.9%
उत्तराखंड	219	15	2	10	192	6.8%	0.9%	4.6%	87.7%
पश्चिम बंगाल	902	148	25	92	637	16.4%	2.8%	10.2%	70.6%
केंद्र शासित प्रदेश									
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10	0	1	2	7	0.0%	10.0%	20.0%	70.0%
चंडीगढ़	18	2	0	0	16	11.1%	0.0%	0.0%	88.9%
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1	0	0	0	1	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
जम्मू और कश्मीर	119	7	2	5	105	5.9%	1.7%	4.2%	88.2%
लद्दाख	20	0	3	0	17	0.0%	15.0%	0.0%	85.0%
लक्षद्वीप	1	0	0	0	1	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
पुदुचेरी	13	3	0	1	9	23.1%	0.0%	7.7%	69.2%

स्रोत: पीएसयू ओएमसीज़ की ओर से आईओसीएल

*** (मैं)आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, रेलवे, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह को प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी जाती हैं ताकि उनके हाउसिंग टाउनशिप/सोसाइटी में रहने वाले परिवारों को एलपीजी सप्लाई की जा सके। ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप मार्केटिंग प्लान के बाहर दी जाती हैं।**
(ii) **मार्केटिंग प्लान से पहले, डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिना आरक्षण के दिए जाते थे।**
(iii) **ऑपरेशन विजय (ओवीएसएस) और मुंबई शहीदों के परिवारों को सीधे डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी गईं, जो मार्केटिंग प्लान से बाहर थीं।**
 # ओबीसी कैटेगरी के तहत 27% **का रिज़र्वेशन 24**/07/2012 **से शुरू किया गया था और ओएमसीज़ ने बाद के एडवर्टाइज़मेंट में इसे लागू किया।**

अनुलग्नक – 2

"ईंधन बिक्री केंद्रों हेतु आवंटन" के संबंध में श्री मनोज कुमार द्वारा दिनांक 12.02.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2186 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुलग्नक।

दिनांक 01.02.2026 की स्थिति के अनुसार राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की संख्या एससी/एसटी/ओबीसी/ओपन-ओएमसी

बीपीसीएल

राज्य	वितरकों की कुल संख्या	एससी श्रेणी के अंतर्गत वितरक	एसटी श्रेणी के अंतर्गत वितरक	ओबीसी कैटेगरी के तहत डिस्ट्रीब्यूटर #	खुला/ अन्य *	एससी कैटेगरी के तहत % डिस्ट्रीब्यूटर	एसटी कैटेगरी के तहत % डिस्ट्रीब्यूटर	ओबीसी कैटेगरी के तहत % डिस्ट्रीब्यूटर	ओपन/अन्य कैटेगरी के तहत % डिस्ट्रीब्यूटर
आंध्र प्रदेश	253	33	14	25	181	13.0%	5.5%	9.9%	71.5%
अरुणाचल प्रदेश	4	0	1	0	3	0.0%	25.0%	0.0%	75.0%
असम	104	11	11	13	69	10.6%	10.6%	12.5%	66.3%
बिहार	494	100	5	69	320	20.2%	1.0%	14.0%	64.8%
छत्तीसगढ़	112	7	13	15	77	6.3%	11.6%	13.4%	68.8%
दिल्ली	78	17	0	0	61	21.8%	0.0%	0.0%	78.2%
गोवा	18	2	0	1	15	11.1%	0.0%	5.6%	83.3%
गुजरात	237	16	26	23	172	6.8%	11.0%	9.7%	72.6%
हरियाणा	190	43	0	22	125	22.6%	0.0%	11.6%	65.8%
हिमाचल प्रदेश	27	3	0	2	22	11.1%	0.0%	7.4%	81.5%
झारखंड	124	7	12	7	98	5.6%	9.7%	5.6%	79.0%
कर्नाटक	325	54	12	31	228	16.6%	3.7%	9.5%	70.2%
केरल	201	31	4	9	157	15.4%	2.0%	4.5%	78.1%
मध्य प्रदेश	367	30	32	43	262	8.2%	8.7%	11.7%	71.4%
महाराष्ट्र	801	72	58	75	596	9.0%	7.2%	9.4%	74.4%
मणिपुर	5	0	2	1	2	0.0%	40.0%	20.0%	40.0%
मेघालय	10	0	9	0	1	0.0%	90.0%	0.0%	10.0%
मिजोरम	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
नागालैंड	9	0	6	0	3	0.0%	66.7%	0.0%	33.3%

ओडिशा	234	29	26	30	149	12.4%	11.1%	12.8%	63.7%
पंजाब	216	44	0	12	160	20.4%	0.0%	5.6%	74.1%
राजस्थान	349	44	28	34	243	12.6%	8.0%	9.7%	69.6%
सिक्किम	3	0	0	1	2	0.0%	0.0%	33.3%	66.7%
तमिलनाडु	422	96	3	43	280	22.7%	0.7%	10.2%	66.4%
तेलंगाना	201	31	13	20	137	15.4%	6.5%	10.0%	68.2%
त्रिपुरा	1	0	1	0	0	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
उत्तर प्रदेश	1040	227	3	109	701	21.8%	0.3%	10.5%	67.4%
उत्तराखंड	59	13	1	5	40	22.0%	1.7%	8.5%	67.8%
पश्चिम बंगाल	336	53	13	44	226	15.8%	3.9%	13.1%	67.3%
केंद्र शासित प्रदेश									
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
चंडीगढ़	3	0	0	0	3	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2	0	0	0	2	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
जम्मू और कश्मीर	42	2	1	5	34	4.8%	2.4%	11.9%	81.0%
लद्दाख	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
पुदुचेरी	8	1	0	1	6	12.5%	0.0%	12.5%	75.0%

स्रोत: पीएसयू ओएमसीज़ की ओर से आईओसीएल

*** (मैं)आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, रेलवे, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह को प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी जाती हैं ताकि उनके हाउसिंग टाउनशिप/सोसाइटी में रहने वाले परिवारों को एलपीजी सप्लाई की जा सके। ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप मार्केटिंग प्लान के बाहर दी जाती हैं।**
(ii) **मार्केटिंग प्लान से पहले, डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिना आरक्षण के दिए जाते थे।**
(iii) **ऑपरेशन विजय (ओवीएसएस) और मुंबई शहीदों के परिवारों को सीधे डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी गईं, जो मार्केटिंग प्लान से बाहर थीं।**
 # ओबीसी कैटेगरी के तहत 27% **का रिज़र्वेशन 24**/07/2012 **से शुरू किया गया था और ओएमसीज़ ने बाद के एडवर्टाइज़मेंट में इसे लागू किया।**

अनुलग्नक – 2

"ईंधन बिक्री केंद्रों हेतु आवंटन" के संबंध में श्री मनोज कुमार द्वारा दिनांक 12.02.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2186 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुलग्नक।

दिनांक 01.02.2026 की स्थिति के अनुसार राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की संख्या एससी/एसटी/ओबीसी/ओपन-ओएमसी

एचपीसी

राज्य	वितरकों की कुल संख्या	एससी श्रेणी के अंतर्गत वितरक	एसटी श्रेणी के अंतर्गत वितरक	ओबीसी कैटेगरी के तहत डिस्ट्रीब्यूटर #	खुला/ अन्य *	एससी कैटेगरी के तहत % डिस्ट्रीब्यूटर	एसटी कैटेगरी के तहत % डिस्ट्रीब्यूटर	ओबीसी कैटेगरी के तहत % डिस्ट्रीब्यूटर	ओपन/अन्य कैटेगरी के तहत % डिस्ट्रीब्यूटर
आंध्र प्रदेश	444	55	19	48	322	12.4%	4.3%	10.8%	72.5%
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
असम	66	5	12	9	40	7.6%	18.2%	13.6%	60.6%
बिहार	491	84	4	75	328	17.1%	0.8%	15.3%	66.8%
छत्तीसगढ़	159	13	24	14	108	8.2%	15.1%	8.8%	67.9%
दिल्ली	48	0	0	0	48	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
गोवा	32	8	0	0	24	25.0%	0.0%	0.0%	75.0%
गुजरात	247	17	28	23	179	6.9%	11.3%	9.3%	72.5%
हरियाणा	139	27	0	12	100	19.4%	0.0%	8.6%	71.9%
हिमाचल प्रदेश	32	3	2	3	24	9.4%	6.3%	9.4%	75.0%
झारखंड	142	15	16	17	94	10.6%	11.3%	12.0%	66.2%
कर्नाटक	375	56	16	31	272	14.9%	4.3%	8.3%	72.5%
केरल	147	31	4	4	108	21.1%	2.7%	2.7%	73.5%
मध्य प्रदेश	388	30	37	34	287	7.7%	9.5%	8.8%	74.0%
महाराष्ट्र	833	86	61	68	618	10.3%	7.3%	8.2%	74.2%
मणिपुर	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
मेघालय	4	0	4	0	0	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%

मिजोरम	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
नागालैंड	5	0	4	0	1	0.0%	80.0%	0.0%	20.0%
ओडिशा	297	28	30	36	203	9.4%	10.1%	12.1%	68.4%
पंजाब	171	35	0	12	124	20.5%	0.0%	7.0%	72.5%
राजस्थान	379	53	32	35	259	14.0%	8.4%	9.2%	68.3%
सिक्किम	3	0	0	0	3	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
तमिलनाडु	316	67	4	27	218	21.2%	1.3%	8.5%	69.0%
तेलंगाना	249	34	23	16	176	13.7%	9.2%	6.4%	70.7%
त्रिपुरा	3	0	0	1	2	0.0%	0.0%	33.3%	66.7%
उत्तर प्रदेश	876	198	2	86	590	22.6%	0.2%	9.8%	67.4%
उत्तराखंड	39	4	1	3	31	10.3%	2.6%	7.7%	79.5%
पश्चिम बंगाल	366	64	18	41	243	17.5%	4.9%	11.2%	66.4%
केंद्र शासित प्रदेश									
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
चंडीगढ़	5	2	0	0	3	40.0%	0.0%	0.0%	60.0%
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	5	1	0	0	4	20.0%	0.0%	0.0%	80.0%
जम्मू और कश्मीर	114	10	3	5	96	8.8%	2.6%	4.4%	84.2%
लद्दाख	5	0	4	0	1	0.0%	80.0%	0.0%	20.0%
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
पुदुचेरी	9	3	0	0	6	33.3%	0.0%	0.0%	66.7%

स्रोत: पीएसयू ओएमसीज़ की ओर से आईओसीएल

*** (मैं)आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, रेलवे, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह को प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी जाती हैं ताकि उनके हाउसिंग टाउनशिप/सोसाइटी में रहने वाले परिवारों को एलपीजी सप्लाई की जा सके। ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप मार्केटिंग प्लान के बाहर दी जाती हैं।**
(ii) **मार्केटिंग प्लान से पहले, डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिना आरक्षण के दिए जाते थे।**
(iii) **ऑपरेशन विजय (ओवीएसएस) और मुंबई शहीदों के परिवारों को सीधे डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी गईं, जो मार्केटिंग प्लान से बाहर थीं।**
 # ओबीसी कैटेगरी के तहत 27% **का रिज़र्वेशन 24**/07/2012 **से शुरू किया गया था और ओएमसीज़ ने बाद के एडवर्टाइज़मेंट में इसे लागू किया।**

अनुलग्नक – 3

"ईंधन बिक्री केंद्रों हेतु आवंटन" के संबंध में **श्री मनोज कुमार** द्वारा दिनांक 12.02.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2186 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुलग्नक।

	दिनांक 01.02.2026 की स्थिति के अनुसार एससी/एसटी/ओबीसी/ओपन को 2014 से 2026 तक अलॉट किए गए आरओज़ (एलओआई जारी किए गए लेकिन चालू नहीं हुए) की संख्या - पीएसयू ओएमसीज़																	
क्र. स.	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश**	**एससी श्रेणी**				**एसटी श्रेणी**				**ओबीसी श्रेणी**				**ओपन / अन्य श्रेणी**				**कुल एलओआईज़**
		आईओसीएल	**बीपीसीएल**	**एचपीसीएल**	**कुल**	**आईओसीएल**	**बीपीसीएल**	**एचपीसीएल**	**कुल**	**आईओसीएल**	**बीपीसीएल**	**एचपीसीएल**	**कुल**	**आईओसीएल**	**बीपीसीएल**	**एचपीसीएल**	**कुल**	**कुल**
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	0	3	5	0	0	5	9
2	आंध्र प्रदेश	71	72	37	180	38	31	15	84	44	54	41	139	109	121	78	308	711
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	20	20	10	50	0	0	0	0	11	4	3	18	68
4	असम	10	17	15	42	30	29	23	82	28	28	40	96	64	58	70	192	412
5	बिहार	274	133	108	515	20	9	5	34	183	94	102	379	365	192	181	738	1666
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3
7	छत्तीसगढ़	30	21	15	66	67	56	39	162	61	39	25	125	152	145	90	387	740
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1	0	0	1	5	3	6	14	3	0	1	4	7	5	6	18	37
9	दिल्ली	6	6	2	14	0	0	0	0	6	2	8	16	22	18	15	55	85
10	गोवा	1	2	2	5	2	8	2	12	3	2	5	10	9	19	16	44	71
11	गुजरात	60	45	56	161	173	98	88	359	108	69	77	254	264	188	199	651	1425
12	हिमाचल प्रदेश	37	19	17	73	8	6	3	17	13	16	16	45	67	33	34	134	269
13	हरियाणा	241	152	130	523	0	0	0	0	108	88	83	279	309	251	199	759	1561
14	जम्मू और कश्मीर	17	13	11	41	24	17	11	52	15	21	19	55	67	32	53	152	300
15	झारखंड	17	10	17	44	48	48	20	116	46	33	32	111	83	69	69	221	492
16	कर्नाटक	223	194	116	533	108	50	48	206	145	133	116	394	367	277	276	920	2053
17	केरल	146	71	57	274	24	9	9	42	100	60	64	224	233	123	120	476	1016
18	लद्दाख	0	1	0	1	3	1	1	5	0	1	0	1	1	1	0	2	9

19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
20	महाराष्ट्र	266	235	195	696	156	146	127	429	235	244	230	709	571	563	500	1634	3468
21	मेघालय	0	0	0	0	55	56	40	151	0	0	0	0	10	13	8	31	182
22	मणिपुर	0	0	0	0	3	5	1	9	1	5	0	6	1	9	3	13	28
23	मध्य प्रदेश	93	56	57	206	130	92	68	290	135	96	86	317	342	252	256	850	1663
24	मिजोरम	0	0	0	0	27	25	13	65	0	0	0	0	2	2	2	6	71
25	नागालैंड	0	0	0	0	17	17	5	39	0	0	0	0	5	2	1	8	47
26	उड़ीसा	38	26	28	92	55	33	32	120	43	35	35	113	167	80	85	332	657
27	पंजाब	80	76	48	204	0	0	0	0	21	40	41	102	175	134	104	413	719
28	पुदुचेरी	14	9	2	25	0	0	0	0	7	6	2	15	11	7	6	24	64
29	राजस्थान	146	126	151	423	114	115	97	326	185	178	173	536	405	393	375	1173	2458
30	सिक्किम	1	2	0	3	3	6	2	11	5	0	1	6	8	3	2	13	33
31	तेलंगाना	64	53	44	161	44	44	36	124	37	74	63	174	110	148	142	400	859
32	तमिलनाडु	186	180	87	453	10	6	5	21	98	136	58	292	229	255	144	628	1394
33	त्रिपुरा	2	3	2	7	8	7	2	17	8	8	2	18	9	14	10	33	75
34	उत्तर प्रदेश	548	389	272	1209	17	17	11	45	404	348	285	1037	864	741	514	2119	4410
35	उत्तरांचल	24	15	10	49	4	2	4	10	12	9	13	34	64	50	36	150	243
36	पश्चिम बंगाल	74	73	28	175	16	14	6	36	41	47	36	124	136	140	97	373	708
	सोर्स - इंडस्ट्री के आधार पर बीपीसीएल																	

अनुलग्नक – 4

"ईंधन बिक्री केंद्रों हेतु आवंटन" के संबंध में **श्री मनोज कुमार** द्वारा दिनांक 12.02.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2186 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुलग्नक।

दिनांक 01.02.2026 की स्थिति के अनुसार एससी/एसटी/ओबीसी/OPEN को 2014 से 2026 तक अलॉट की गई एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप (एलओआई जारी किए गए लेकिन चालू नहीं किए गए) की संख्या - ओएमसीज़ के लिए

		आईओसी					बीपीसी					एचपीसी					कुल				
क्र. स.	राज्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	खुला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल योग	अन्य पिछड़ा वर्ग	खुला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल योग	अन्य पिछड़ा वर्ग	खुला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल योग	अन्य पिछड़ा वर्ग	खुला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल योग
1	आंध्र प्रदेश	1	0	1	1	3	0	0	0	0	0	3	7	0	1	11	4	7	1	2	14
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	0	2	0	0	2	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3	0	1	4
4	बिहार	0	1	0	1	2	0	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0	2	2	1	5
5	छत्तीसगढ़	0	3	0	0	3	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5
6	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	गुजरात	0	6	1	0	7	0	1	0	1	2	0	2	0	2	4	0	9	1	3	13
9	हरियाणा	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
10	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	2
11	झारखंड	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	1	0	1	4	3	1	0	2	6
12	कर्नाटक	0	2	2	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	2	0	5
13	केरल	1	3	2	0	6	0	1	0	0	1	0	2	1	0	3	1	6	3	0	10
14	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
15	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	0	1	3	0	3	0	2	5
16	मणिपुर	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
17	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
19	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ओडिशा	1	2	0	1	4	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	1	3	1	1	6
21	पंजाब	0	3	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	2	0	5
22	राजस्थान	2	0	0	0	2	0	5	0	0	5	1	1	0	0	2	3	6	0	0	9
23	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24	तमिलनाडु	0	3	2	0	5	0	2	1	0	3	2	1	1	0	4	2	6	4	0	12
25	तेलंगाना	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	4	1	0	5	0	5	1	1	7
26	त्रिपुरा	1	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3
27	उत्तर प्रदेश	0	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	3	2	0	5
28	उत्तराखंड	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
29	पश्चिम बंगाल	2	8	2	0	12	0	4	4	0	8	1	2	1	2	6	3	14	7	2	26
	केंद्र शासित प्रदेश											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	जम्मू और कश्मीर	0	2	0	0	2	0	1	0	0	1	0	2	0	0	2	0	5	0	0	5
5	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	लक्षद्वीप	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
7	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

सोर्स - इंडस्ट्री के आधार पर आईओसीएल